नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 042
दि. 11.06.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'विफलता कांग्रेस की, कलंक हिन्दुओं पर...', पीएम मोदी ने यूं याद दिलाई धीमी ग्रोथ रेट

(जीएनएस)।

राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA) कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये 'कांग्रेस ग्रोथ रेट' और 'NDA ग्रोथ रेट' का अंतर है. कांग्रेस की कार्यशैली पर प्रश्न उठाते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी. आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 वर्ष पूरा करने पर देश की जनता को नमन किया है इसके साथ ही धीमी विकास दर के लिए उन्होंने कांग्रेस को फटकार लगाई है. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज में धीमी विकास की रफ्तार को बड़ी चतुराई से 'हिंदू ग्रोथ रेट' का नाम दे दिया गया. पीएम मोदी ने कहा कि ये कार्यशैली कांग्रेस की थी, दायित्व कांग्रेस का था, असफलता कांग्रेस की थी लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया. जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट.

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि "2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे. इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है. मैं आज देश की महान जनता को नमन करता हूं, जनता-जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं."

पीएम मोदी ने NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2014 में जब ठऊअ की जीत हुई थी तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है. इस आशा का इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था. देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपने भरोसा हमें सौंपा था. मुझे आज संतोष है गर्व है कि ठऊअ परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है."

विफलता कांग्रेस की, कलंक हिन्दू आबादी के नाम...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठऊअ के 12 वर्षों की सफलता को गिनाते हुए कहा कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है. कांग्रेस ने देश को

लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था.

उन्होंने आगे कहा, "देश को यह एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे-धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है और बड़ी ही चतुराई से धीमी विकास को एक नाम दिया था, 'हिंदू ग्रोथ रेट' यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट. इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में न सुशासन था, न नीति, न नीयत और ना निर्णय."

2004 की NDA की हार को याद करते हुए आगे PM मोदी ने कहा कि, "पहली बार अटल जी के नेतृत्व में ठऊअ सरकार आई तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया. विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ों रुपये के घोटालों में घसीट दिया. देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में NDA की सरकार बनी. देश ने देखा कि जब नीयत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है..."

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सवाल ये है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ? ये 'कांग्रेस ग्रोथ रेट' और 'ठऊअ ग्रोथ रेट' का अंतर है. एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी. आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है. एक व्यवस्था काम अटकाती-भटकाती थी. आज की व्यवस्था कहती है, काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा और इसलिए 2014 से 2026 की कहानी केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जिसने पहली बार अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ना तय किया है..."

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के समय में जब हर तरह हाहाकार मचा हुआ था तो भारत ने उस हालत का सफलता से मुकाबला किया और आगे बढ़ा. पीएम मोदी ने कहा कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं तो भारत 7.7 प्रतिशत से आगे बढ़ रहा है. ये सफलता इतनी आसान नहीं है. कल के विकसित भारत की गारंटी है आज का आकांक्षी भारत.

हिन्दू विकास दर क्या है?

हिन्दू विकास दर भारतीय अर्थव्यवस्था की उस धीमी वृद्धि को कहा जाता है जो स्वतंत्रता के बाद लगभग 1950 से 1980 के दशक तक चली. इस अवधि में भारत की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर तीन से साढ़े 3 प्रतिशत के आसपास रही, जबकि प्रति व्यक्ति आय वृद्धि 1.3 प्रतिशत से भी कम थी.

अब 3 महीने में निपटाने होंगे आर्थिक अपराध के मामले, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए निर्देश

(जीएनएस)।

लखनऊ। आर्थिक अपराध के मामलों को तीन माह के भीतर निस्तारित किया जाएगा। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों को तीन माह से अधिक समय तक लंबित न रखा जाए।

वित्तीय धोखाधड़ी, जालसाजी, गबन और अन्य आर्थिक अपराध न केवल सरकारी संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आम नागरिकों के विश्वास को भी आघात पहुंचाते हैं। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अपने सरकारी आवास पर ईओडब्ल्यू के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ईओडब्ल्यू को आधुनिक तकनीक की मदद से जांच प्रणाली को और सशक्त बनाना होगा।

उन्होंने कहा कि तीन माह से अधिक समय तक जांच अपने पास रखने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। साथ ही यह नियम बनाया जाए कि कोई भी अधिकारी तीन माह से अधिक समय तक किसी मामले को लंबित नहीं रखेगा।

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष 31 मई तक ईओडब्ल्यू ने 155 मामलों की जांच पूरी की है, जबकि 71 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। बैठक में केस मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस डिजिटल प्रणाली से मामलों के ऑनलाइन प्रबंधन व रियल टाइम मानिटरिंग में सुविधा हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित व्यवस्था से जांच की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि बदलते तकनीकी परिवेश में वित्तीय धोखाधड़ी, निवेश संबंधी ठगी, पोंजी स्कीम, मल्टीलेवल मार्केटिंग, चिट-फंड घोटाले और साइबर फ्रॉड जैसे अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करना आवश्यक है।

माइक बंदङ्घकान में फुसफुसाहट और पर्ची! सीएम योगी-रामभद्राचार्य के बीच सीक्रेट बातचीत ने बढ़ाई हलचल

लखनऊ में आयोजित एक राम कथा कार्यक्रम के दौरान ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जगदुरु रामभद्राचार्य के बीच हुई एक खास बातचीत चर्चा का विषय बन गई है. दरअसल, मंच पर जब सीएम योगी आचार्य से मिलने पहुंचे, तो जगदुरु रामभद्राचार्य ने माइक को बंद करवाकर उनके कान में कुछ गुप्त बातचीत की. इतना ही नहीं उन्होंने सीएम योगी को एक पर्ची भी सौंपी, जिसे मुख्यमंत्री ने ध्यान से पढ़कर अपने पास रख लिया. इस पूरे घटनाक्रम के बाद वहां मौजूद लोगों में उत्सुकता बढ़ गई।

बम की धमकी के बाद फैली दहशत, मेयर ऑफिस, बीएसई और बीएमसी दफ्तर निशाने पर, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

(जीएनएस)।

मुंबई में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब बृहद मुंबई महानगरपालिका (BMC/MCGM) के वरिष्ठ अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिला। यह ईमेल सुबह करीब 9:21 बजे भेजा गया था, जिसमें शहर के कई प्रमुख ठिकानों पर बम धमाकों की धमकी दी गई थी। इस घटना के सामने आते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गईं।

ईमेल में दावा किया गया कि दिनभर अलग-अलग समय पर विस्फोट किए जाएंगे। इसमें दोपहर 1:11 बजे मेयर कार्यालय और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को उड़ाने की धमकी दी गई, जिसका उद्देश्य "भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना" बताया गया। इसके बाद 2:11 बजे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय और 3:11 बजे विभिन्न इटउ दफ्तरों को निशाना बनाने की बात कही गई।

धमकी भरे संदेश में खालिस्तान से जुड़े संदर्भ और 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी उल्लेख किया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार वह सैन्य कार्रवाई थी जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को हटाने के लिए की गई थी, जिसके बाद पंजाब में लंबे समय तक उग्रवाद का दौर चला।

धमकी को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। हालांकि ईमेल की सत्यता की पुष्टि अभी की जा रही है, लेकिन किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इटउ मुख्यालय, मेयर रितु तवड़े के कार्यालय और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया है।

बढ़ाई गई सुरक्षा

पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं। शहर के महत्वपूर्ण आर्थिक और प्रशासनिक केंद्रों पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

पश्चिम बंगाल : कांग्रेस में विलय करने जा रही है ममता बनर्जी? मर्जर की खबरों पर क्या बोली तृणमूल कांग्रेस पार्टी

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी उथल-पुथल के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) और कांग्रेस के संभावित विलय की चर्चाओं ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हालांकि, दोनों दलों ने बुधवार, 10 जून को इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि कांग्रेस और TMC के विलय का कोई प्रस्ताव न तो विचाराधीन है और न ही इस दिशा में कोई औपचारिक बातचीत चल रही है।

इसके बावजूद राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि दोनों दल भविष्य में संभावित चुनावी सहयोग और साझा राजनीतिक मुद्दों पर साथ काम करने के विकल्प खुले रखे हुए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस और TMC के शीर्ष नेताओं के बीच लगातार संवाद बना हुआ है।

कांग्रेस और TMC के विलय की अटकलों को उस समय और बल मिला जब हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि विपक्षी राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बैठक का उद्देश्य विपक्षी एकजुटता और INDIA गठबंधन को मजबूत करना था, न कि किसी प्रकार का संगठनात्मक विलय।

ANI के मुताबिक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बीच भी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने विपक्षी दलों के बीच बेहतर समन्वय और INDIA गठबंधन को मजबूत बनाने पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने अगस्त में हैदराबाद में होने वाली अगली INDIA गठबंधन बैठक को लेकर भी सहमति जताई है। इससे संकेत मिलते हैं कि भले ही विलय की संभावना नहीं है, लेकिन विपक्षी एकता के लिए दोनों दल साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक- इन अटकलों के पीछे एक बड़ी वजह TMC के भीतर चल रहा गंभीर राजनीतिक संकट भी माना जा रहा है। पार्टी इस समय अपने गठन के बाद के सबसे बड़े आंतरिक विद्रोह का सामना कर रही है।

बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी का दावा है कि TMC के 58 विधायक खुलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। बाद में उन्होंने यह संख्या बढ़कर 64 विधायकों तक पहुंचने का दावा भी किया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि पार्टी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती दी है और इसी कारण विभिन्न राजनीतिक संभावनाओं पर चर्चाएं तेज हुई हैं।

सिर्फ विधायक ही नहीं, बल्कि TMC के कुछ सांसदों के बीच भी असंतोष के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा और TMC की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पार्टी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने भी पार्टी और उच्च सदन दोनों से इस्तीफा दे दिया। इन घटनाओं ने ळटउ नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है और विपक्षी राजनीति में नए समीकरणों की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है।

लोकसभा में अलग बैठने की मांग

TMC की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि लोकसभा में पार्टी के 20 सांसदों ने अलग बैठने की व्यवस्था की मांग करते हुए स्पीकर को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा,"हम 20 सांसद हैं और हमने लोकसभा अध्यक्ष से अलग बैठने की व्यवस्था का अनुरोध किया है।

हम पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों के साथ मिलकर काम करेंगे।"

राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने 9 जून को जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इसमें उन्होंने समावेशी विकास, लैंगिक समानता और सामाजिक संवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित गतिविधियों में 9 जून 2026 को हुई चर्चाओं और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों की श्रृंखला में भागीदारी के माध्यम से एक मजबूत और समन्वित राजनयिक उपस्थिति रही।

जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने नेपाल के युवा, श्रम और रोजगार मंत्री श्री रामजी यादव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नेपाल ने भारत के डिजिटल पोर्टलों की सराहना की। भारत ने इस बात पर बल दिया कि हमारी "पड़ोसी प्रथम" नीति के अंतर्गत नेपाल भारत का एक प्राथमिकता वाला साझेदार बना हुआ है। दोनों मंत्रियों ने कौशल विकास, श्रम गतिशीलता और डिजिटल प्रौद्योगिकी साझा करने के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस चर्चा में दोनों देशों के श्रमिकों के लिए अवसरों और कल्याण को बढ़ाने और दीर्घकालिक और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

युवा संगम छठे चरण कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल का महाराष्ट्र दौरा

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम के अंतर्गत 'युवा संगम' के छठे चरण कार्यक्रम के अंतर्गत, तिरुपति स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुणे स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान-आईआईएसईआर का दौरा किया। पांच दिनों के कार्यक्रम में प्रतिभागियों को महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शैक्षिक उत्कृष्टता, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और विकासात्मक उपलब्धियों का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला।

खान सर विवाद में नया मोड़, रौशन आनंद की जमानत अर्जी पर होगा तगड़ा ड्रामा, कब आएगा बड़ा फैसला? बीते दिनों कई बार विरोध प्रदर्शन

(जीएनएस)।

पटना में खान सर की कोचिंग से जुड़े फायरिंग और बवाल मामले में गिरफ्तार किए गए शिक्षक रौशन आनंद की कानूनी लड़ाई अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद अब उनकी जमानत याचिका जिला जज की अदालत में दाखिल की गई है। इस मामले को लेकर छात्रों में लगातार नाराजगी देखी जा रही है और बीते दिनों कई बार विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं।

दूसरी ओर खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जबकि खुद खान सर को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिल चुकी है। ऐसे में इस पूरे मामले पर सभी की नजरें अदालत के अगले फैसलों पर टिकी हुई हैं।

रौशन आनंद की जमानत याचिका सोमवार को मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उनके वकीलों ने जिला जज की अदालत का रुख किया है। अब नई जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और अदालत यह तय करेगी कि उन्हें राहत मिल सकती है या नहीं। पुलिस ने रौशन आनंद को 3 जून को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई 2 जून को खान सर की कोचिंग के बाहर हुए हमले और गोलीबारी की घटना के बाद की गई थी।

रौशन आनंद की गिरफ्तारी के विरोध में छात्र लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब तक पटना में तीन बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं। मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन में छात्रों ने सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि बिना किसी निष्पक्ष जांच समिति के किसी व्यक्ति को जेल भेजना सही नहीं है। उनका कहना था कि पहले पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए।

छात्रों ने यह भी कहा कि रौशन आनंद से जुड़े हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान यह सवाल भी उठाया गया कि एक आरोपी को जमानत मिल जाती है जबकि दूसरे को जेल में रखा जाता है। छात्रों का दावा था कि जो व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था, वह जेल में है जबकि अन्य लोग बाहर हैं।

इसी मामले में खान सर के दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिका पर बुधवार को फिर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से केस डायरी और दोनों आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी मांगी थी। अदालत ने दोनों गार्ड्स की बेल पेटीशन खारिज कर दी है।

सुनवाई के दौरान जिला अभियोजक की ओर से प्रदीप कुमार के हथियार के उपयोग पर सवाल उठाए गए थे।

लखनऊ हाईकोर्ट सख्त, गुमशुदा नाबालिग बच्चों के मामलों में पुलिस कमिश्नर से मांगा स्पष्टीकरण; जानें मामला

(जीएनएस)।

लखनऊ, हाईकोर्ट ने राजधानी में गुमशुदा नाबालिग बच्चों के मामलों की जांच में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा गया और नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। अधिकांश बच्चों को बरामद कर लिया गया है, जबकि शेष मामलों में खोज अभियान और जांच तेज करने को कहा गया है।

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी से गुम हुए नाबालिग बच्चों के मामलों में लचर तफ्तीश पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने लखनऊ के सभी थानों से संबंधित ऐसे गुमशुदगी के मामलों में पुलिस कमिश्नर से 10 जून को स्पष्टीकरण मांगा था। साथ ही पुलिस उपायुक्त (डी सी पी) दीक्षा शर्मा को निर्देश दिया थाकि वे ऐसे केसों की निगरानी कर रिपोर्ट पेश करें।

इसके तहत, बुधवार को अदालत को बताया गया कि 1 जनवरी2026 से अब तक कुल 261 लोग लखनऊ से गुम हुए हैं। इनमें अधिकांश नाबालिग

लड़के व लड़कियां हैं। इनमें 227 का पता लगाकर बरामद कर लिया गया है। जबकि, 34 अभी भी लापता हैं। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाकर इन लापता लोगों के मामलों की साप्ताहिक निगरानी करने के निर्देश दिए और 3 जुलाई की निगरानी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। जब राजधानी में गुमशुदा लोगों की तलाश मामले में यह हाल है, तो ने जिलों की हालत समझी जा सकती है। कोर्ट के आदेश पर लखनऊ के पूर्वी जो के डी सी पी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी समेत ऐसे मामलो के विवेचक भी पेश हुए। कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाकर कहा कि ऐसे मामलों को विवेचना में सुस्ती, लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।

न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की अवकाश कालीन पीठ ने बुधवार को यह आदेश एक नाबालिग लड़की की और से उसके पिता द्वारा दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में शहर से गुम हुई 12 साल की नाबालिग लड़की की तलाश करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया था।

इस नाबालिग लड़की बरामदगी होने पर कोर्ट ने उसके पिता को सौंप दिया। पहले, सुनवाई के समय पेश हुईं डी सी पी दीक्षा शर्मा ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया था कि उनकी अधिकारिता में आने वाले नौ थानों में से 81 लड़कियों (जिनमें अधिकांश नाबालिग हैं), का या तो अपहरण हुआ या फिर वे बहला फुसलाकर भगा ले जाई गईं।

इनमें से 66 को बरामद कर लिया गया है, जबकि, 15 लड़कियां अभी भी गुम हैं। इसपर कोर्ट ने कहा था कि, मौजूदा मामले के अलावा शहर में अन्य और ऐसे मामले हो सकते हैं, जो पुलिस की जानकारी में नहीं होंगें। ऐसे में डी सी पी इन मामलों का पता लगाकर और इनकी निगरानी करके तीन दिन में रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 जून को पहले केस के रूप में निर्धारित करके डी सी पी को सभी संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारियों, प्रभारी निरीक्षकों समेत विवेचनाधिकारियों के साथपेश होने का निर्देश दिया था।

पांच लाख रुपए प्रतिमाह वेतन के बाद भी नहीं टिक रहे हैं डॉक्टर, 40 फीसदी पद हैं खाली; बनेगा नया भर्ती बोर्ड

(जीएनएस)।

लखनऊ , यूपी के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के करीब 18,500 पद हैं। इसमें करीब 11 हजार कार्यरत हैं, जबकि 7,500 पद खाली चल रहे हैं।

प्रदेश में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के करीब 18,500 पद हैं। इसमें करीब 11 हजार कार्यरत हैं, जबकि 7,500 पद खाली चल रहे हैं। करीब 2500 विशेषज्ञों के लिए भर्ती प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी भेजा गया है। ग्रामीण इलाके में विशेषज्ञों की कमी का ग्राफ करीब 70 फीसदी तक है।

अपनाई जा रही है वैकल्पिक व्यवस्था

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रिवर्स बिडिंग शुरू की गई है। इसमें पांच लाख रुपया प्रतिमाह के हिसाब से विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। पिछले वर्ष करीब 170 डॉक्टरों की भर्ती की गई थी। इन्हें फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) में चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजा गया है। वॉक-इन-इंटरव्यू के तहत जनवरी 2026 में संविदा पर 710 डॉक्टरों की भर्ती के लिए साक्षात्कार हुए हैं। विभाग में सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया गया था।

बन रहा है भर्ती बोर्ड

डॉक्टरों की कमी और आयोग से भर्ती में लगने वाले लंबे वक्त को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड लेवल 2 यानी एमडी-एमएस डिग्रीधारी विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करेगा। साथ ही लेवल वन यानी एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सकों की पदोन्नति की प्रक्रिया भी पूरी करेगा।

डॉक्टरों की कमी के मुख्य कारण

हर साल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में करीब 200-250 विशेषज्ञ चिकित्सक भेजे जाते हैं। इसमें करीब 25 फीसदी कार्यभार ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही गायब हो जाते हैं। लंबे समय तक गायब होने के बाद इन्हें नोटिस दी जाती है, लेकिन जब नहीं लौटते हैं तो बर्खास्तगी की कार्रवाई करके उस पद को रिक्त घोषित किया जाता है। ग्रामीण इलाके से नौकरी छोड़ने वाले विशेषज्ञों ने बताया कि उन्हें आवास, बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा जैसी आधारभूत सुविधा नहीं मिलती है। तमाम अस्पतालों में उपचार में प्रयोग होने वाले संसाधन भी नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में सरकारी सेवा छोड़ना विवशता होती है। निजी अस्पतालों में शहरी सुविधा के साथ ही आकर्षक वेतन भी मिलता है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

प्रदेश में कई स्तर पर डॉक्टरों की भर्ती चल रही है। नया बोर्ड भी बन रहा है। नए मेडिकल कॉलेजों से निकलने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर भी कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि साल दो साल में सभी पद भर जाएंगे। हमारी कोशिश है कि मरीजों को बेहतर इलाज मिले।-अमित कुमार घोष, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

भीषण गर्मी के बीच कटौती से उपभोक्ता हुए उग्र, आधी रात को उपकेंद्रों का घेराव; कर्मियों ने खुद को किया बंद

(जीएनएस)।

लखनऊ , यूपी की राजधानी लखनऊ में बिजली संकट बना हुआ है। चार हजार उपभोक्ताओं की बिजली सोमवार रात 11:30 से मंगलवार की सुबह 4:30 बजे तक बाधित रही।

दुबग्गा क्षेत्र के एफसीआई उपकेंद्र तहत आदर्श विहार फीडर से जुड़े लगभग चार हजार उपभोक्ताओं की बिजली सोमवार रात 11:30 से मंगलवार की सुबह 4:30 बजे तक बाधित रही। उमस भरी गर्मी में घंटों बिजली गुल रहने से नाराज उपभोक्ता आधी रात में उपकेंद्र पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। स्थिति बिगड़ती देख उपकेंद्र के कर्मचारियों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने उपभोक्ताओं को समझाकर शांत कराया और जल्द बिजली आपूर्ति बहाल कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद लोग लौट गए। कर्मचारियों ने बताया कि बिजली चोरी के चलते ओवरलोडिंग के कारण कई इलाकों में केबल जलने से आपूर्ति बार-बार बाधित होती है जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है।

15 कर्मचारियों पर 26 हजार उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी

एफसीआई उपकेंद्र पर मौजूदा समय में 15 कर्मचारी हैं। दिन और रात की पाली में सात-सात कर्मचारी कार्य करते हैं। इन पर 26 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी है। कर्मचारियों के अनुसार यहां 30 कर्मियों की जरूरत है। उच्च अधिकारियों की उदासीनता से उपकेंद्र पर आए दिन हंगामे की स्थिति बनती है लेकिन समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

एक के बाद एक जले दो ट्रांसफार्मर

दुबग्गा क्षेत्र के प्रतीक विहार कॉलोनी में 250 केवीए ट्रांसफार्मर में आग लगने से करीब एक घंटे तक आग की लपटें उठती रहीं। इससे अफरातफरी का माहौल बना रहा। लपटों में 10 मीटर केबल भी जल गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। विभाग ने 400 केवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया लेकिन ओवरलोडिंग के कारण वह भी कुछ घंटों बाद फुंक गया। इससे करीब 10 घंटे तक लोगों को गर्मी-उमस में बिजली संकट से जूझना पड़ा सोमवार को तीसरा ट्रांसफार्मर लगाया गया जिसके बाद शाम को बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी।

15 दिन से लो वोल्टेज की समस्या

दुबग्गा पारा क्षेत्र के मुनेश्वरपुरम कॉलोनी में पिछले 15 दिन से हाई और लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। क्षेत्र में एबीसी और न्यूट्रल जलने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। जिम्मेदार इसका स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

केबल जलने से कई इलाकों की बिजली गुल

जीपीआरए उपकेंद्र के अंतर्गत जानकीपुरम चार नंबर चौराहे के पास पोल पर लगे केबल में आग जलने से 400 केवीए ट्रांसफार्मर से जुड़े उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इसी प्रकार सोमवार रात करीब 11:30 बजे फैजुल्लागंज की श्याम विहार कॉलोनी में प्रजापति टावर के पास और मंगलवार शाम करीब 7 बजे परागी मंदिर के सामने भी केबल में आग लगने की घटनाएं हुईं। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने केबल बदलकर आपूर्ति चालू की।

15 मिनट के लिए बंद हुए 11 उपकेंद्र, मचा हड़कंप

ट्रांस गोमती क्षेत्र में मंगलवार रात करीब 9:30 बजे 11 उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति अचानक ठप हो गई। इससे सीतापुर रोड के बिठौली से लेकर खड़ा तक और जानकीपुरम से लेकर निराला नगर तक 15 मिनट अंधेरा छाया रहा। घटना से इलाके के बिजली अभियंताओं में हड़कंप मच गया। ट्रांसमिशन इकाई के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि आंधी और बिजली कड़कने के कारण ट्रांसमिशन उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति अपने आप बंद हो गई जो 15 मिनट के बाद 9:45 बजे चालू हुई। इस दौरान अहिबरनपुर, न्यू कैंपस, इंजीनियरिंग कॉलेज, जानकीपुरम, विकास नगर, जीएसआई, जीपीआरए पुरनिया, निराला नगर, महानगर और कपूरथला उपकेंद्र प्रभावित रहे।

सेना में भर्ती कराने के आरोप में एक का कोर्ट मार्शल, दूसरा दोषमुक्त; रक्षा मंत्रालय ने दिए जांच के निर्देश

(जीएनएस)।

लखनऊ। पांच साल पहले कमांड अस्पताल में तैनाती के दौरान सेना में भर्ती कराने के नाम पर नौ लाख रुपये लेने के एक आरोप में पकड़े गए दो जवानों की जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस मामले में बीती 29 मई को 11 जीआरआरसी में आयोजित जनरल कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया को एक जवान को दोषी मानते हुए उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया है।

जवान को पांच साल की सजा और सेना से सेवामुक्त कर दिया गया है। जबकि इसी आरोप में सह अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया गया है। एक ही आरोप में सह आरोपी को दोषमुक्त किये जाने की शिकायत के बाद फिर से मध्य कमान मुख्यालय को जांच कराने के लिए रक्षा मंत्रालय ने पत्र भेजा है।

सेना मेडिकल कोर के हवलदार हरिओम सिंह चौहान की तैनाती अप्रैल 2018 से जून 2021 तक कमांड अस्पताल में थी। आरोप है कि सुरेश यादव उर्फ बबलू यादव से उनकी बेटी की मिलिट्री नर्सिंग सेवा में भर्ती कराने

के लिए हवलदार हरिओम सिंह चौहान के बैंक खाते में नौ लाख रुपये भेजे गए थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हवलदार हरिओम सिंह चौहान को गिरफ्तार कर मोबाइल फोन की जांच की। जांच में सुरेश यादव की बेटी का प्रवेश पत्र मिला, जिसे एएमसी के ही हवलदार भूपेंद्र यादव ने भेजा था।

मिलिट्री इंटेलिजेंस से असम से हवलदार भूपेंद्र यादव को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। मध्य यूपी सब एरिया मुख्यालय के आदेश पर दिसंबर 2022 से 11 गोरखा राइफल्स रेजीमेंटल सेंटर में संबद्ध कर दोनों जवानों के खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हुई।

समरी ऑफ एविडेंस में दोनों जवानों के मोबाइल फोन में प्रवेश पत्र पाए गए। हवलदार हरिओम सिंह चौहान ने ट्रायल के दौरान कहा कि उसका पत्नी से तलाक होने वाला था, तलाक में प्रतिपूर्ति के लिए ही कुछ लोगों से रुपये उधार लिया गया था, इसमें से करीब साढ़े चार लाख रुपये वापस कर दिए गए।

वहीं, सुरेश यादव उर्फ बबलू यादव की पत्नी रानी देवी ने ट्रायल के दौरान कहा कि उनके परिचित और लखनऊ में ईएमई कोर में तैनात कुलदीप यादव ने हवलदार भूपेंद्र यादव से मुलाकात करायी थी। भूपेंद्र यादव ने कहा था कि हवलदार हरिओम सिंह चौहान बेटी को मिलिट्री नर्सिंग में भर्ती कराने में मदद करेंगे।

इसके लिए 10 लाख रुपये मांगे गए लेकिन डील नौ लाख रुपये में तय हुई। बेटी ने भर्ती का फार्म भरा। प्रवेश पत्र आया तो भूपेंद्र यादव को भेजा गया। भूपेंद्र ने ही हवलदार हरिओम सिंह चौहान के मोबाइल फोन पर प्रवेश पत्र भेजा था।

गोरखपुर में बैठक के बाद भी नहीं ढके गए नाले, खुली नगर निगम की पोल

सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बावजूद नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और जल निगम इस नाले की जिम्मेदारी लेने से मुकर रहे हैं.

(जीएनएस)।

गोरखपुरः करीब 2 साल पहले बारिश के दौरान लखनऊ में खुले नाले में गिरकर हुई एक बच्चे की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नगर निगम क्षेत्रों में खुले नालों को ढकने का सख्त निर्देश दिया था. बावजूद इसके गोरखपुर में लापरवाही लगातार जारी है और इस तरह की दर्दनाक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं.

गोरखपुर में भी ऐसी कई घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं जिनमें सीधे तौर पर नगर निगम और ठेकेदारों की लापरवाही सामने आती है. लेकिन किसी भी प्रकार का कड़ा एक्शन ना होने से ऐसा प्रतीत होता है कि सीएम के निर्देशों का जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है.

मुख्यमंत्री के दौरे के बाद भी नहीं सुधरे हालातः अभी 2 जून को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर थे और उन्होंने इस गंभीर विषय को लेकर कड़ी आपत्ति जताते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए थे. लेकिन अनुपालन की बात तो दूर, लापरवाही इस कदर हावी थी कि मंगलवार 9 जून की देर शाम एक और व्यक्ति ने खुले नाले में गिरकर दम तोड़ दिया. इससे पूर्व भी पादरी बाजार से पिपराइच रोड पर निमार्णाधीन खुले नाले में गिरने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी. शाहपुर थाना क्षेत्र के रासी नगर में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी जिसमें एक मासूम बच्चे ने अपनी जान गवाई थी.

डीएम आवास के पास भी खुले मिले मौत के नालेः रासी नगर की उस घटना में खुले नाले में गिरने से निर्माण कार्य की सरिया मासूम के पेट में घुस गई थी. ईटीवी भारत ने इस घटना के बाद जब शहर के खुले नालों की जमीनी पड़ताल शुरू की तो सबसे चौकाने वाला नजारा सामने आया.

पड़ताल में पता चला कि खुद जिलाधिकारी (डीएम) आवास और कार्यालय को जाने वाली वीआईपी सड़क के किनारे के नाले भी बिना ढक्कन के खुले पड़े मिले. यहां पास के कोचिंग संस्थान के बच्चे अपनी गाड़ियां भी खड़ी करते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है.

सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर हो रही सफाईः ऐसी ही जानलेवा स्थिति शहर में कई अन्य जगहों पर भी साफ तौर पर दिखाई दी. यही नहीं, नगर निगम की लापरवाही इस दौरान यह भी देखने को मिली कि गहरे 15 फीट के नाले में बिना किसी सुरक्षा मानक, मास्क और ग्लब्स के बगैर ही सफाई कर्मचारियों से काम लिया जा रहा था. इस अव्यवस्था पर बेतियाहाता क्षेत्र के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने भी कड़ी आपत्ति जताई है. इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वे कूड़े को नालों में न फेंकें.

अपर नगर आयुक्त ने दिया कार्रवाई का आश्वासनः जब ईटीवी भारत इस गंभीर समस्या को अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार के संज्ञान में लाया तो वह पहले तो चलाए जा रहे सफाई अभियान की बातें करने लगे. लेकिन जब उन्हें जिलाधिकारी आवास और कार्यालय की तरफ बिना ढक्कन के खुले नालों की सच्चाई दिखाई गई तो वह सहम गए. इसके बाद उन्होंने बात संभालते हुए कहा कि इसको दिखवाएंगे और दो दिन के भीतर यहां मजबूत ढक्कन लगवा दिया जाएगा. अब मंगलवार 9 जून को हुई ताजा घटना के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है.

जिम्मेदारी लेने से मुकर रहे शहर के विभागः जिस नाले में गिरकर 40 वर्षीय शख्स की मौत हुई है, उसकी जिम्मेदारी लेने को शहर का कोई भी प्रमुख विभाग तैयार नहीं है. ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर लावारिस छोड़ दिया गया यह नाला है किसका. फातिमा अस्पताल के पास बने इस नाले के निर्माण से नगर निगम ने साफ तौर पर अपना हाथ खींच लिया है. नगर निगम के अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार का कहना है कि यह नाला नगर निगम के अधिकार क्षेत्र का नहीं है.

PWD और जल निगम ने भी पल्ला झाड़ाः दूसरी तरफ जल निगम के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार का स्पष्ट कहना है कि यह नाला उनके विभाग का नहीं है. तो लोक निर्माण विभाग (PWD) खंड तीन के अधिशासी अभियंता उदय प्रकाश भी कहते हैं कि यह नाला पीडब्ल्यूडी का नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गोरखपुर शहर में कोई बाहर से आकर गुपचुप तरीके से नाला बनाता है और चला जाता है. और किसी भी जिम्मेदार सरकारी विभाग को इसकी भनक तक नहीं होती.

अज्ञात मृतक की पहचान में जुटी शाहपुर पुलिसः फिलहाल इस ताजा हादसे में जिस व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है, अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और शाहपुर थाना पुलिस पहचान में जुटी है. वहीं स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी गुस्सा है कि नाले पर तुरंत स्लैब पड़ना चाहिए था, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाया है. हैरानी की बात यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता धीरज गुप्ता कहते हैं कि शाहपुर क्षेत्र में खुले नाले में गिरने से हुई इस घटना के बाद भी शहर और जिला प्रशासन में कोई हलचल तक नहीं हुई. इसके लिए दोषी कौन है और सजा किसे मिलेगी, यह सवाल आज भी अनुत्तरित खड़ा है.

सरिया धंसने से पहले भी हो चुकी हैं कई मौतेंः खुले नाले में गिरकर किसी आम नागरिक के मर जाने की यह शहर में कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले 12 मई को देवरिया जिले के निवासी मजदूर हंसराज की पादरी बाजार में नाले में गिरकर मौत हो गई थी. वह नाला भी निमार्णाधीन था और उसे ढकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे हंसराज के शरीर में सरिया धंस गई थी. इसी तरह चिलुआताल क्षेत्र के मानबेला में 18 फरवरी को कन्हैया नाम का एक बालक साइकिल सहित खुले नाले में गिर गया था और सरिया धंस जाने से उसकी भी मौत हो गई थी.

अधिकारियों के कागजी दावों की खुली पोलः बीते 15 मई को भी बरगदवा में पैदल जा रहा एक व्यक्ति अचानक खुले नाले में गिर गया था, लेकिन आसपास के लोगों ने देख लिया और उसे सकुशल बाहर निकाल दिया. ये घटनाएं तो महज एक बानगी हैं, क्योंकि शहर में अन्य कई हादसे ऐसे हो चुके हैं जिनमें लोग खुले नाले में गिरकर जान गंवा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं. शायद ऐसी ही घटनाओं को लेकर 2 जून की उच्च स्तरीय बैठक में जिम्मेदारों ने गहरी चिंता जताई थी. उस बैठक में मंथन के बाद फैसला लिया गया था कि खुले नालों पर शीघ्र स्लैब डलवा दिए जाएंगे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए.

सिर्फ वादों में उलझकर रह गए सीएम के निर्देशः शासन ने भी इसे बेहद गंभीरता से लिया था और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे रखा है कि नाले ढके जाने में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए. लेकिन लेटलतीफी और घोर लापरवाही की वजह से मंगलवार को भी एक ऐसी ही दर्दनाक घटना दोबारा घट गई. पादरी बाजार क्षेत्र में फातिमा बाईपास के पास खुले नाले में एक अज्ञात युवक गिर गया, जिसकी सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवक को नाले से बाहर निकलवाकर एम्बुलेंस के जरिए तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

लापरवाही के कारण उजड़ रहे हंसते-खेलते परिवारः अगर सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारियों ने समय रहते अमल किया होता, तो मंगलवार को पादरी बाजार में एक और बेकसूर युवक की जान नहीं जाती. सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि वह युवक कौन था और कहां का निवासी था, इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है. युवक के अपने परिजन घर पर उसके सकुशल लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे. लेकिन अव्यवस्थाओं को सही करने के जिम्मेदार अधिकारियों को ऐसी मौतों पर कोई दर्द नहीं होता है और ये मामले सिर्फ दावों और दिशा-निर्देशों में ही उलझ कर रह जाते हैं. यदि समय रहते जवाबदेही तय नहीं हुई तो बारिश का सीजन करीब होने के कारण ऐसी घटनाएं अभी और बढ़ सकती हैं.

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने होम्योपैथी पर जिम्मेदार विमर्श की सलाह दी, सत्यापित सूचना पर भरोसा करने का किया आह्वान

एनसीएच ने सभी हितधारकों से आग्रह किया है कि वे होम्योपैथी और पंजीकृत चिकित्सकों के खिलाफ मानहानिकारक, भ्रामक और निराधार बयान देने से बचें

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) ने एक सलाह जारी कर सभी हितधारकों, मीडिया संस्थानों और आम जनता से आग्रह किया है कि वे होम्योपैथी और पंजीकृत होम्योपैथ के बारे में सोच-समझकर बयान जारी करें।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष डॉ. तारकेश्वर जैन ने सूचित किया कि आयोग होम्योपैथी में शिक्षा, अभ्यास, पेशेवर आचरण और नैतिकता के मानकों को विनियमित करने और बनाए रखने के अपने दायित्व का प्रयोग करते हुए होम्योपैथी और इसके चिकित्सकों को लक्षित करने वाले गैर-जिम्मेदाराना और निराधार बयानों के खिलाफ दिनांक 08.06.2026 को एफ. नंबर 27/2026-एनसीएच के माध्यम से एक परिपत्र जारी किया है।

आयोग ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रसारित हो रहे अपमानजनक, मानहानिकारक, भ्रामक और निराधार बयानों के मामलों का संज्ञान लेते हुए विमर्श में तथ्यात्मक सटीकता और जिम्मेदार संचार की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ. जैन ने बताया कि होम्योपैथी राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली है और होम्योपैथिक दवाओं का विनियमन औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत होता है। उन्होंने बताया कि होम्योपैथी में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक ढांचे के तहत संचालित किए जाते हैं और इसमें दाखिला राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) उत्तीर्ण उम्मीदवारों के माध्यम से होता है।

उन्होंने कहा कि पंजीकृत होम्योपैथ निर्धारित शिक्षा और प्रशिक्षण मानकों से गुजरते हैं और लागू वैधानिक तथा नियामक प्रावधानों के अनुसार होम्योपैथी का अभ्यास करने के लिए अधिकृत हैं।

आयोग ने संस्थानों, पेशेवर निकायों, स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों, मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे होम्योपैथी या इसके चिकित्सकों के संबंध में सार्वजनिक बयान देने से पहले उचित सावधानी बरतें और तथ्यों की सटीकता सुनिश्चित करें।

विमर्श में कहा गया है कि किसी व्यक्तिगत चिकित्सक के आचरण के संबंध में किसी भी आरोप, शिकायत या चिंता का समाधान पेशे के खिलाफ सामान्यीकृत दावों की बजाय स्थापित वैधानिक, नियामक, अनुशासनात्मक या न्यायिक तंत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए।

डॉ. जैन ने होम्योपैथी और पंजीकृत चिकित्सकों की गरिमा, अखंडता और कानूनी स्थिति की रक्षा के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि निराधार, भ्रामक या मानहानिकारक बयान फैलाने के कृत्यों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है, इसमें जहां आवश्यक हो वहां कानूनी कार्रवाई भी शामिल है।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

पीओके में पाक सेना की बर्बरता

पाक अधिवृत कश्मीर (पीओके) की पुलिस और सैन्य बलों द्वारा 20 से अधिक प्रदर्शनकारी नागरिकों की हत्या के लिए सीधे इस्लामाबाद को जिम्मेदार ठहराया और विश्व समुदाय से आग्रह किया कि निर्दोष जनता पर अत्याचार का पाकिस्तान को दोषी ठहराएं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाईं प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने भी गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान के सुरक्षाबलों की बर्बरता की निन्दा की।

दरअसल सोमवार को पीओके के रावलाकोट में सेना ने प्रदर्शनकारी नागरिकों पर फायरिंग करके 120 लोगों को मार डाला था जबकि पुलिस ने पूरे गुलाम कश्मीर में कईं स्थानों पर हुए प्रदर्शन को बूरतापूर्वक दबाने के लिए बल प्रयोग किया जिसमें काफी लोग मारे गए और ज्यादातर घायल बताए जा रहे हैं। असल में पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर में विदेशी मीडिया पर रोक लगा रखी है। विदेशी मिशन के राजनायिकों को भी इस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं मिलती। रही बात मानवाधिकार संगठनों की तो पाकिस्तान जैसे देश में मानवाधिकारवादियों के लिए मानवाधिकार तो आतंकियों और जल्लाद सैन्य कर्मियों के ही होते हैं। इसीलिए भारत ने विश्व समुदाय से अनुरोध किया है कि पाकिस्तान द्वारा गुलाम कश्मीर के लोगों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन उस क्षेत्र में जाकर वास्तविकता को देखें।

सच तो यह है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ यही आवाज विश्व मंचों पर बहुत पहले ही उठाना चाहिए थी। आखिर पीओके भी तो जम्मू-कश्मीर का ही हिस्सा है और जम्मू-कश्मीर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत वैधानिक विलय के बाद भारत का अभिन्न अंग है। यह तो भारत का अधिकार है कि वह बलपूर्वक कब्जाए गए जिस भूभाग के निवासियों पर इस्लामाबाद की सरकार के इशारे पर लाठी, गोली और बम से हमला वदी वाले भेंड़ियों ने किया, उनकी निन्दा करे क्योंकि जिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है वे हमारे अपने हैं।

मजे की बात तो यह है कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पहले भी कह चुके हैं कि हमारे लोगों पर पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है। मतलब यही है गुलाम कश्मीर के लोग भी उतने ही भारतीय हैं जितने कि जम्मू-कश्मीर के भारतीय।

बहरहाल भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को गुलाम कश्मीर में सरकारी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है, इसकी आशंका सोमवार को पाकिस्तान की मीडिया में व्यक्त की गईं थी। मीडिया चैनलों पर बैठकर पूर्व सैन्य अधिकारियों, राजनायिकों व पत्रकारों ने दो टूक शब्दों में स्वीकार किया कि पाक सेना की हैवानियत की वजह से अब भारत को बहुत अच्छा अवसर मिल गया है और वे पाक सेना की बर्बरता का मुद्दा जोर-शोर से उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी शिकायत करें।

पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों ने पाक सेना और सरकार को जमकर लताड़ा। लब्बोलुआब यह है कि भारत को गुलाम कश्मीर की पीड़ित जनता के साथ खड़ा होने का समय आ गया है। बेहतर तो यह होता कि यदि पाकिस्तान पीओके को नहीं संभाल पा रहा है तो उसे इस क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए। किन्तु पाकिस्तान से ऐसी शराफत की उम्मीद नहीं की जा सकती। उम्मीद तो यही है कि गुलाम कश्मीरी शीघ्र ही आजादी पाने के लिए वूर पाक सैनिकों को अपनी जमीन से भागने पर मजबूर कर देंगे।

उ.प्र. चुनाव से पहले योगी का आ गया 'त्रिशूल' फॉमूर्ला... धड़ाधड़ एनकाउंटर, गरजे बुलडोजर और सनातन के रथ पर होंगे सवार!

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात बिछते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना सबसे आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. सूबे में एक तरफ जहां माफियाओं पर धड़ाधड़ एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन से कानून व्यवस्था का चक्रव्यूह तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ 'कट्टर हिंदुत्व' के एजेंडे को धार देकर विपक्ष के पीडीए फॉमूर्ले को ध्वस्त करने की बड़ी तैयारी है.

(जीएनएस)।

लखनऊ. देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने में बेशक 7-8 महीने का वक्त है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी से ही राज्य की राजनीतिक बिसात पर अपने सबसे घातक मोहरे चलने शुरू कर दिए हैं. विपक्ष के जातिगत समीकरणों ढऊऊ यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सोशल इंजीनियरिंग की काट ढूंढने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पुराने और सबसे भरोसेमंद ह्याकालभैरव अवतारह्न में लौट आए हैं. इस बार उनकी रणनीति दोगुनी आक्रामक है, जहां एक तरफ अपराधियों की रीढ़ तोड़ने के लिए बुलडोजर और एनकाउंटर की रफ्तार बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ बहुसंख्यक समाज को एकजुट करने के लिए ह्याकट्टर हिंदुत्वह्न के मुद्दे को चुनावी पिच पर सबसे आगे रख दिया गया है. राजनीतिक पंडितों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने इस बार ह्यत्रिशूल रणनीतिह्न तैयार की है, जो कानून-व्यवस्था, राष्ट्रवाद-हिंदुत्व और धड़ाधड़ लिए जा रहे प्रशासनिक फैसलों पर टिकी है.

पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सूबे के बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एनकाउंटर ड्राइव को तेज कर दिया है. गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्य प्रताप चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर से लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पैर में गोली लगने की घटनाएं अचानक अब रूटीन बन चुकी हैं. सिर्फ अपराधी ही नहीं, बल्कि उनके अवैध निमार्णों और जमीनों पर मुख्यमंत्री का पसंदीदा ह्याब्रांड बुलडोजरह्न दोबारा पूरी ताकत

से गरजने लगा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है.

योगी के एक्शन पर सपा का दो टूक जवाब, जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और विपक्ष ने इन एनकाउंटरों को ह्याप्रायोजितह्न बताकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो सीएम योगी ने दो टूक लहजे में साफ कर दिया कि 'जो भी कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानून अपने सबसे सख्त दायरे में रहकर काम करेगा, समाज के दुश्मनों के लिए कोई सहानुभूति नहीं होगी.'

विकास और सुशासन के दावों के साथ-साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी रैलियों में ह्यसनातन और हिंदुत्वह्न के एजेंडे को बेहद धारदार बना दिया है. मऊ और लखनऊ की हालिया जनसभाओं में उनके बयानों ने साफ कर दिया है कि वे चुनाव को ध्रुवीकरण और सांस्कृतिक गौरव के मुद्दे पर ले जाने की पूरी तैयारी में हैं.

योगी सभाओं में क्या कह रहे हैं?

सीएम योगी अपने भाषणों में जनता को सीधे संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि 'आपका एक वोट केवल सरकार नहीं चुनता, बल्कि आपके एक वोट की ताकत ने 500 साल की गुलामी के कलंक को धोकर अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया है. यही एक वोट यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाता है.' इसके जरिए वे बंटे हुए हिंदू वोट बैंक को जातिगत दीवारों से ऊपर उठाकर एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं.

योगी का तीसरा और अंतिम प्रहार

योगी धड़ाधड़ प्रशासनिक फैसले और युवाओं को साधने की कोशिश में लग गए हैं. चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने युवाओं और सरकारी व्यवस्था को लेकर कई कड़े और त्वरित फैसले लिए हैं. जैसे पेपर लीक पर सख्त कानून. परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त से सख्त जेल और जुमार्ने का प्रावधान. नौसेना शौर्य वाटिका जैसे सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद से जुड़े प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के साथ युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर देने का रोडमैप तैयार किया जा रहा है.

जानकारों की राय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भली-भांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए उन्हें अपने मूल ह्याफायरब्रांडह्न और ह्याकड़क प्रशासकह्न वाले नैरेटिव पर ही दांव लगाना होगा. अपराधियों पर प्रशासनिक चाबुक और मंचों से हिंदुत्व की हुंकार, यही वह चक्रव्यूह है जिसमें वे विपक्ष के जातिगत समीकरणों को उलझाना चाहते हैं.

ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासी जंग बेहद तीखी होने वाली है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग होगी, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का ह्याकालभैरव अवतारह्न और उनका आजमाया हुआ बुलडोजर मॉडल होगा.

भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेषों की ऐतिहासिक 10 दिवसीय प्रदर्शनी मंगोलिया में संपन्न

मंगोलिया में लगभग एक लाख श्रद्धालुओं ने अर्हंत सारिपुत्र और अर्हंत मौद्गल्यायन के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए

(जीएनएस)।

भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों, अर्हंत सारिपुत्र और अर्हंत मौद्गल्यायन के पवित्र अवशेष आज मंगोलिया के उलानबातर स्थित गंडन तेगचेनलिंग मठ में आयोजित दस दिवसीय सफल प्रदर्शनी के बाद भारत वापस लाए गए हैं। गंडन तेगचेनलिंग मठ के अनुरोध पर, संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय ने मध्य प्रदेश सरकार, श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी और इंटरनेशनल बुद्धिष्ट कॉन्फेडरेशन (आईबीसी) के सहयोग से 31 मई से 9 जून, 2026 तक पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का आयोजन किया। यह प्रदर्शनी 31 मई, 2026 को मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आम जनता के लिए खोली गई।

पवित्र अवशेषों को 30 मई, 2026 को असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य द्वारा मंगोलिया के शिक्षा मंत्री श्री एनख-अमगलान और गंडांटेगचेनलिंग मठ के परम पूज्य खंबा नोमुन खान गेशे लहारम्पा डी जावजांडोरज को समारोहपूर्वक सौंपा गया।

इस प्रदर्शनी की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अक्टूबर 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री खुरेलसुख उखना की भारत यात्रा के दौरान की थी। भारत और मंगोलिया बौद्ध धर्म पर आधारित गहरे सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध साझा करते हैं और इस प्रदर्शनी ने मंगोलिया के लोगों को पवित्र अवशेषों के दर्शन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। 10 दिनों तक चली इस प्रदर्शनी के दौरान, मंगोलिया भर से लगभग एक लाख श्रद्धालुओं ने मठ में दर्शन किए। मंगोलिया की जनसंख्या लगभग 34 लाख है।

अब तक ये अवशेष केवल थाईलैंड और मंगोलिया भेजे गए हैं। गौरतलब है कि जून 2022 में मंगोलिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी एक बेहद सफल और यादगार आयोजन था।

प्रदर्शनी के दौरान, भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और इंटरनेशनल बुद्धिष्ट कॉन्फेडरेशन ने बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया, जिनकी जनता, भिक्षुओं और विद्वानों द्वारा बहुत सराहना की गई:

i) सारिपुत्त और मोग्गलाना झ ज्ञान, भक्ति और अवशेषों की यात्रा झ इंटरनेशनल बुद्धिष्ट कॉन्फेडरेशन द्वारा

ii) भारत से मंगोलिया तक: आंतरिक एशिया में बुद्ध धम्म का प्रसार - इंटरनेशनल बुद्धिष्ट कॉन्फेडरेशन द्वारा

iii) प्रकाश के पात्र: प्रतिमा विज्ञान, अवशेष और धम्म का मार्ग (भारत के संग्रहालय संग्रहों के माध्यम से शाक्यमुनि बुद्ध की यात्रा) - भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा

पवित्र अवशेषों को प्रोटोकॉल और सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा प्राप्त है। इन्हें 30 मई, 2026 को भारतीय वायु सेना के एक विशेष विमान द्वारा मंगोलिया लाया गया था, जिसमें असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था। आज भारतीय वायु सेना के एक विशेष विमान द्वारा लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इन अवशेषों को भारत वापस लाया गया। गंडन तेगचेनलिंग मठ में औपचारिक स्वागत और विदाई समारोह आयोजित किए गए।

मंगोलिया सरकार ने प्रदर्शनी के लिए पूर्ण समर्थन दिया, जबकि गंडन तेगचेनलिंग मठ ने पवित्र अवशेषों की आदरणीय स्थिति के अनुरूप आयोजन के धार्मिक पहलुओं की देखरेख की। आज मठ में आयोजित समापन समारोह के दौरान, परम पूज्य खंबा नोमुन खान गेशे लहारम्पा डी. जावजांदोरज, महामहिम श्री एनख-अमगलान, लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना, श्रीलंका के महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष पूज्य बनगला उपतिस्सा थेरो और इंटरनेशनल बुद्धिष्ट कॉन्फेडरेशन के महासचिव शारत्से खेनसुर रिनपोचे जांगचुप चोडेन सहित वक्ताओं ने मंगोलिया में प्रदर्शनी को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

पवित्र अवशेषों को भारत वापसी से पहले, परम पूज्य श्री एनख-अमगलान और परम पूज्य वेन. खंबा नोमुन खान गेशे लहारम्पा डी. जावजांदोरज द्वारा लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना को विधिवत सौंप दिया गया। प्रस्थान से पहले हवाई अड्डे पर, मंगोलिया में भारत के राजदूत श्री अतुल मलहारी गोत्सुर्वे ने लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल को एक मंगोलियाई पौधा भेंट किया। यह पौधा लद्दाख में भारत और मंगोलिया के बीच अटूट मित्रता और आध्यात्मिक बंधन के प्रतीक के रूप में लगाया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल और गंडन तेगचेनलिंग मठ ने प्रदर्शनी के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग के लिए मंगोलिया स्थित भारतीय दूतावास का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन ने भारत और मंगोलिया के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया है।

क्या है बेन स्टोक्स का नाइट क्लब विवाद? करियर खत्म होने का खतरा, मुश्किल में इंग्लैंड के कप्तान

(जीएनएस)।

इंग्लैंड क्रिकेट इस समय एक बड़े विवाद के केंद्र में है। टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स का नाम एक नाइट क्लब घटना से जुड़ने के बाद सुर्खियों में है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब इंग्लैंड एंड वेल्स को जांच शुरू करनी पड़ी है और क्रिकेट जगत में स्टोक्स की कप्तानी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है, लेकिन इस विवाद ने इंग्लैंड क्रिकेट में हलचल जरूर मचा दी है। इंग्लैंड ने हाल ही में न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट में हराया था। जीत के बाद कप्तान बेन स्टोक्स, तेज गेंदबाज गस एटकिंस और कुछ रग्बी खिलाड़ी लंदन के चेल्सी इलाके में स्थित एक नाइट क्लब पहुंचे। रिपोर्ट्स के अनुसार एउइ द्वारा लागू किए गए आधी रात की पाबंदी के बावजूद खिलाड़ी देर रात तक क्लब में मौजूद रहे।

मारपीट की नौबत आई

इसके बाद क्लब के श्क्ढ एरिया में विवाद हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रग्बी खिलाड़ी ने कथित

तौर पर एटकिंसन को निशाना बनाकर मुक्का चलाया, लेकिन वह एउइ के एक सुरक्षा अधिकारी को जा लगा। हालांकि अब तक किसी रिपोर्ट में स्टोक्स या एटकिंसन को झगड़े की शुरूआत करने वाला नहीं बताया गया है।

ECB अभी क्या कर रहा है?

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर "टीम प्रोटोकॉल के उल्लंघन" की जांच शुरू कर दी है। बोर्ड ने कहा है कि वह घटना की पूरी जानकारी जुटा रहा है और क्रिकेट रेगुलेटर को भी सूचित कर दिया गया है। दूसरे टेस्ट के लिए टीम चयन और खिलाड़ियों की उपलब्धता पर फैसला जांच के बाद लिया जाएगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि स्टोक्स और एटकिंसन दूसरे टेस्ट से बाहर भी हो सकते हैं, हालांकि एउइ ने अभी तक कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं किया है।

क्या कप्तानी पर खतरा है?

फिलहाल इसका जवाब हां है, खतरा है लेकिन फैसला नहीं हुआ है। ब्रिटिश मीडिया की कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्टोक्स अपनी कप्तानी के भविष्य पर विचार कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि वह कप्तानी छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं।

इसके पीछे सिर्फ यह घटना नहीं है। पिछले एक साल में इंग्लैंड टीम की "ड्रिंकिंग कल्चर" को लेकर कई विवाद सामने आए थे, जिसके बाद एउइ ने कर्फ्यू जैसे नियम लागू किए थे। ऐसे में अगर कप्तान ही नियम तोड़ते पाए जाते हैं तो मामला और गंभीर माना जा रहा है।

क्या करियर पर भी खतरा है?

अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि स्टोक्स का अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म होने वाला है। न तो पुलिस केस दर्ज हुआ है और न ही उन पर किसी शारीरिक हमले का आरोप है। जांच मुख्य रूप से टीम नियमों के उल्लंघन पर केंद्रित है। हालांकि अगर एउइ कड़ा रुख अपनाता है तो उन्हें निलंबन, जुमार्ना या कप्तानी से हटाए जाने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। करियर समाप्त होने की बातें फिलहाल केवल अटकलें हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

मानव सुथार अब इंग्लैंड में खेलेंगे, रातोंरात खुली किस्मत और आया बुलावा, डेब्यू टेस्ट में मचाया था तहलका

(जीएनएस)।

भारतीय क्रिकेट में इन दिनों एक

नया नाम हर किसी की जुबान पर छाया हुआ है और वह नाम राजस्थान के युवा स्पिनर मानव सुथार का है। अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी फिरकी से विरोधियों को घुटने पर लाने वाले मानव सुथार के हाथ एक बड़ा जैकपॉट लगा है।

इस 23 साल के बाएं हाथ के स्पिनर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धमाकेदार शुरूआत करने के ठीक बाद अब इंग्लैंड के मशहूर काउंटी क्लब वॉरिकशायर के साथ एक शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। क्लब ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि मानव सुथार उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं।

करियर का टर्निंग पॉइंट

यह डील मानव सुथार के करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है क्योंकि उन्हें काउंटी चैंपियनशिप के अगले दो महत्वपूर्ण राउंड के लिए टीम में शामिल किया गया है। वॉरिकशायर की टीम इस समय अंक तालिका में चौथे स्थान पर है और खिताब की दौड़ में बनी हुई है।

डेब्यू मैच कौन भूल सकता है

मानव सुथार ने अपने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में महज 33 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे और मैच में कुल 7 विकेट लेकर भारत की ऐतिहासिक जीत की कहानी लिखी थी। उनके इसी लाजवाब प्रदर्शन को देखते हुए इंग्लिश काउंटी क्लब ने उन्हें तुरंत अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया।

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी किया धमाल

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आने से पहले भी मानव का फर्स्ट-क्लास रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है जहां उन्होंने 29 मैचों में 129 विकेट अपने नाम किए हैं। वॉरिकशायर के परफॉर्मेंस डायरेक्टर जेम्स थॉमस ने कहा है कि मानव की फिरकी उनके गेंदबाजी आक्रमण को इंग्लैंड की पिचों पर एक नया और मजबूत आयाम देगी। इंग्लिश कंडीशंस तेज गेंदबाजों के लिए आदर्श होती है लेकिन मानव को शायद पिच से फर्क नहीं पड़ना चाहिए।

मैदान पर कब उतर सकते हैं

वह आगामी 12 से 15 जून तक स्कारबोरो में यॉर्कशायर के खिलाफ होने वाले मैच में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद अगले हफ्ते वे टॉन्टन में सोमरसेट के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। अगस्त में होने वाले भारत के श्रीलंका दौरे से पहले मानव के लिए यह अनुभव बेहद काम आने वाला है।

मुनीर की तानाशाही का नया चेहरा, पीओके प्रदर्शन में नेताओं पर लगाया राजद्रोह, 1 करोड़ का रखा इनाम

(जीएनएस)।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी आजाद जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में व्यापक शटर-डाउन हड़ताल देखने को मिली। इस दौरान पाकिस्तान की एजेंसियों और हाल ही में बैन किए गए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के समर्थकों के बीच कई जगह झड़पें भी हुईं। इसी बीच पाकिस्तान की सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए नया तरीका निकाला है।

प्रदर्शन करने वाले नेताओं पर राजद्रोह का मामला

प्रदर्शन को दबाने के लिए PoK की सरकार ने खअअउ के दो बड़े नेताओं के खिलाफ राजद्रोह की कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही संगठन के चार नेताओं की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वालों के लिए 1 करोड़ रुपये के इनाम की भी घोषणा की गई है। दूसरी ओर, ढङ्गड के प्रधानमंत्री फैसल मुमताज राठौर ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए सभी पक्षों से बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की है।

मीरपुर डिवीजन से शुरू हुआ प्रदर्शन

झड़पों की शुरूआत तब हुई जब मीरपुर डिवीजन के कई इलाकों में JAAC की योजना के तहत रैलियां निकाली गईं। इस डिवीजन में मीरपुर, भीमबर और कोटली जिले शामिल हैं। मीरपुर शहर में सैकड़ों प्रदर्शनकारी कायदे-ए-आजम क्रिकेट स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए। इसके बाद उन्होंने प्लाक ब्रिज की ओर मार्च शुरू किया। यहां कोटली जिले की सीमा पर डड्याल से ख्वाजा मेहरान अरशद के नेतृत्व में आई दूसरी रैली भी उनके साथ जुड़ गई, जिससे प्रदर्शन और बड़ा हो गया।

पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प, कई लोगों की मौत

मीरपुर के बाहरी इलाके पिंड सभरवाल गांव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संक्षिप्त लेकिन तनावपूर्ण झड़प हुई। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार इस दौरान दो पुलिसकर्मी और कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए। सबसे गंभीर और हिंसक झड़पें कोटली शहर में हुईं। यहां खुइरट्टा तहसील से आए सैकड़ों लोगों का जुलूस शहर में पहुंचा था। हालांकि अधिकारी आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों और ढङ्गड कैबिनेट के कुछ सदस्यों ने नाम न बताने की शर्त पर दावा किया कि इन झड़पों में एक डॉक्टर और एक महिला समेत कई लोगों की मौत हुई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं।

छत पर खड़े डॉक्टर को लगी गोली

शुरूआती रिपोर्टों के मुताबिक, मृतकों में शामिल डॉक्टर अपने घर की छत पर मौजूद थे। इसी दौरान झड़प के बीच चली एक आवारा गोली उन्हें लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। पूरे क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं लगातार बंद रहने के कारण वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करना काफी मुश्किल हो गया है।

दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

इस बीच, JAAC के वरिष्ठ सदस्य और जाने-माने वकील अमजद अली खान की कथित गिरफ्तारी के विरोध में ढङ्गड बार काउंसिल के आ'ान पर वकीलों ने न्यायिक कार्यवाही का बहिष्कार किया। इससे कानूनी कामकाज भी प्रभावित हुआ। PoK सरकार ने मुजफ्फराबाद निवासी शौकत नवाज मीर और मीरपुर निवासी मेहरान अरशद ख्वाजा के खिलाफ राजद्रोह की कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी किए निर्देश में दोनों नेताओं पर भाषणों, लिखित सामग्री, वीडियो और ऑडियो के माध्यम से राजद्रोह फैलाने का आरोप लगाया गया है।

पानी की एक-एक बूंद होगी रीसायकल, वसंतकुंज में बनेगा मेट्रो का पहला 'ग्रीन डिपो'

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के तहत राजधानी के वसंतकुंज में एक बेहद आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल डिपो बनाने जा रहा है। इस डिपो की सबसे बड़ी खासियत यहां की 'जीरो डिस्चार्ज' प्रणाली होगी। इसके अलावा, डिपो के भीतर रखरखाव और संचालन को सुगम बनाने के लिए विश्वस्तरीय और अत्याधुनिक तकनीकी प्रणालियों को शामिल किया जा रहा है, जिससे यह डिपो पूरी तरह ईको- फ्रेंडली और हाईटेक नजर आएगा।

हैदराबाद की फर्म को मिला जिम्मा

यूपीएमआरसी ने वसंतकुज में बनने वाले इस अत्याधुनिक डिपो के सिविल निर्माण कार्य के लिए हैदराबाद की प्रतिष्ठित फर्म 'जीएचवी प्रालि' को शॉर्टलिस्ट किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 127 करोड़ रुपये का टेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब जल्द ही धरातल पर काम शुरू होने की उम्मीद है।

पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए डिपो परिसर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहां से किसी भी प्रकार का प्रदूषित या अपशिष्ट जल बाहर नहीं बहेगा।

डुअल प्लंबिंग सिस्टम

डिपो मे साफ पानी और रिसाइकल पानी के प्रवाह के लिए बिल्कुल अलग-अलग पाइपलाइन व्यवस्थाएं होगी।

STP और ETP का कॉम्बिनेशन

सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉट (एसटीपी) और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) को आपस में एकीकृत किया जाएगा, जिससे डिपो से निकलने वाले हर तरह के पानी को साफ कर दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके।

वॉटर टैंक्स की व्यवस्था

दैनिक संचालन और किसी भी आपातकालीन स्थिति (जैसे आग लगना) से निपटने के लिए डिपो में रॉ वॉटर, डोमेस्टिक वॉटर और फायर वॉटर टैंको की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

ये अत्याधुनिक मशीनें

ट्रेनों के रख-रखाव और मरम्मत कार्य को आसान बनाने के लिए डिपो परिसर को हाईटेक गैजेट्स से लैस किया जाएगा।

ऑटोमैटिक पिट जैक

डिपो में पूर्ण ऑटोमैटिक सिंक्रोनाइज्ड पिट जैक और मोबाइल जैक मशीनें लगाई जाएगी, जिससे भारी-भरकम कोचों को आसानी से उठाने-गिराने और मेंटेनेस करने में मदद मिलेगी।

बोगी टर्न टेबल्स

इसकी मदद से कोच के निचले हिस्से (बोगियों) को अलग-अलग पटरियों के बीच आसानी से स्थानातरित (शिफ्ट) किया जा सकेगा।

इलेक्ट्रिक शंटर्स

ये शटर्स डिपो परिसर के अंदर मेट्रो ट्रेनों की नियत्रित और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेंगे।

ऑटोमैटिक वॉशिंग प्लांट

इसके जरिए मेट्रो कोचों की मैकेनाइज्ड और तेजी से सफाई हो सकेगी। साथ ही री-रेलिग व रेस्क्यू व्हीकल्स तकनीकी खराबी आने पर त्वरित सहायता प्रदान करेंगे।

लखनऊ की कठौता झील में कूदे युवक का 26 घंटे बाद मिला शव, पास में मिले कपड़े और चप्पल

(जीएनएस)।

लखनऊ। चिनहट की कठौता झील में सोमवार की दोपहर कूदे वास्तुखंड निवासी 36 वर्षीय मजदूर शिव प्रसाद लोधी का शव मंगलवार शाम बरामद किया गया। 26 घंटे खोजबीन के बाद राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने शव बाहर निकाला है।

वास्तु खंड निवासी 36 वर्षीय शिव प्रसाद सरिये का जाल बांधने का काम करते थे। सोमवार दोपहर वह तीन बजे के करीब वह कठौता झील के पास पहुंचे और अपने कपड़े, चप्पल उतारकर कूद गए। राहगीरों ने उन्हें झील में कूदते देखा तो सूचना चिनहट पुलिस को दी।

पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की लेकिन झील में उनका कोई पता नहीं चला। इस पर सूचना एसडीआरएफ को दी गई।

मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने सोमवार देर शाम तक तलाशी अभियान चलाया लेकिन तलाश नहीं हो सकी। अंधेरा ज्यादा होने पर अभियान रोक दिया गया। मंगलवार की सुबह से दोबारा खोजबीन शुरू हुई। दिन भर चले अभियान के बाद शाम को झील से युवक का शव मिला।

परिवारजन के मुताबिक वह घर से किसी काम पर जाने की बात कह कर निकले थे। सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखंड सौम्या पांडेय ने बताया कि परिवारजन ने फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी है। अगर तहरीर देते हैं तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

यूपी में नशामुक्त भारत अभियान को नई गति, योगी सरकार का व्यापक जनजागरण अभियान

योगी सरकार ने नशामुक्त भारत अभियान को नई गति दी है. 247 हेल्पलाइन 14446 के जरिए 37 हजार से अधिक लोगों को मदद पहुंचाई गई. पुनर्वाद केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है.

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नशामुक्त भारत अभियान को नई गति मिली है. सरकार नशे की समस्या से जूझ रहे युवाओं और नागरिकों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जनजागरण के साथ-साथ हेल्पलाइन, परामर्श और पुनर्वास सुविधाओं का विस्तार कर रही है.

मद्यनिषेध विभाग के माध्यम से चलाए जा रहे 247 हेल्पलाइन नंबर 14446 पर अब तक 37 हजार से अधिक लोगों को सहायता पहुंचाई जा चुकी है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4 लाख से अधिक मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजे गए और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर 232 जागरूकता स्पॉट प्रसारित किए गए.

स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम

सरकार स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम पंचायतों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है. युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है और उन्हें नशा न करने की शपथ दिलाई जा रही है. सोनभद्र और प्रयागराज माघ मेला-2026 में वीडियो वैन का संचालन, 829 सांस्कृतिक कार्यक्रम, 1800 वालपेंटिंग और 1767 गोष्ठियां आयोजित की गईं.

नशा मुक्ति केंद्रों का विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नशा मुक्ति केंद्रों और पुनर्वास सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है. इन केंद्रों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि नशे की लत से मुक्त हुए व्यक्ति समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें.

आर.एल. राजवंशी, राज्य मद्यनिषेध अधिकारी ने कहा, 'नशामुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. हमारा उद्देश्य केवल नशा छुड़वाना नहीं, बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा देकर प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना है.

लखनऊ में इकाना स्टेडियम पर एलडीए का एक्शन... निर्माण से रखरखाव व अनुबंध की शर्तों तक होगी जांच

(जीएनएस)।

लखनऊ स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर चर्चा में है. इस बार वजह कोई क्रिकेट मुकाबला नहीं, बल्कि स्टेडियम के निर्माण, रखरखाव और अनुबंध से जुड़ी शर्तों की जांच है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने स्टेडियम के संचालन और उससे जुड़े निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है.

लखनऊ का इकाना स्टेडियम... वही मैदान जहां चौके-छक्कों की गूंज सुनाई देती है, जहां हजारों दर्शक मैच का रोमांच देखने पहुंचते हैं. लेकिन इस बार चर्चा क्रिकेट की नहीं, बल्कि जांच की हो रही है. कारण है- लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) का एक फैसला.

एलडीए ने इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण, संचालन, रखरखाव और अनुबंध की शर्तों की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित कर दी है. यानी अब स्टेडियम में रिकॉर्ड और फाइलें खंगाली जाएंगी. एलडीए यह पता लगाना चाहता है कि स्टेडियम का संचालन उन शर्तों के मुताबिक हो रहा है या नहीं, जिनके आधार पर इसका अनुबंध किया गया था.

सवाल सिर्फ इमारत का नहीं है. जांच का दायरा काफी बड़ा रखा गया है. समिति यह देखेगी कि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार हुआ या नहीं. स्थिति और अनुबंध से जुड़े सभी पहलुओं का विस्तृत ब्योरा होगा. इसके बाद एलडीए रिपोर्ट की स्टडी करेगा और जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई तय करेगा.

फिलहाल जांच शुरूआती चरण में है और किसी तरह की अनियमितता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन अगर समिति की रिपोर्ट में किसी प्रकार की लापरवाही, निर्माण संबंधी कमी या अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की बात सामने आती है, तो संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

इकाना स्टेडियम सिर्फ लखनऊ ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों में गिना जाता है. यहां अंतरराष्ट्रीय मैचों से लेकर आईपीएल तक के बड़े मुकाबले आयोजित होते हैं. ऐसे में स्टेडियम की निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव को लेकर किसी भी तरह की जांच स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

बरेली में ₹250 करोड़ से बनेगा भव्य टेक्सटाइल पार्कः सीएम योगी की घोषणा के बाद जमीन ट्रांसफर के आदेश, आवेदन शुरू

(जीएनएस)।

बरेली। जिले में टेक्सटाइल पार्क का इंतजार जल्द पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री ने जहां बरेली समेत पांच शहरों में टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की है, वही मिल की भूमि का टेक्सटाइल पार्क के लिए हस्तांतरण का आदेश भी जारी हो गया है। अभी तक यह भूमि सहकारी कताई मिल संघ के पास है। खास बात यह है कि कैबिनेट के आदेश पर भूमि हस्तांतरण निश्शुल्क रूप से किया जाएगा। इसके लिए सहकारी कताई मिल की ओर से भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना में एकीकृत टेक्सटाइल पार्क का लाभ बरेली को भी मिलेगा। जिले में लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इसकी घोषणा कर अंतिम मुहर भी लगा दी।

प्रस्तावित पार्क बहेड़ी से लगभग 10 किलोमीटर दूर नानकपुरी-टांडा मार्ग पर ग्राम सैदपुर खुर्द स्थित उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल परिसर में विकसित किया जाएगा। करीब 79.61 एकड़ क्षेत्रफल में बनने वाला यह पार्क प्रदेश के वस्त्र एवं परिधान उद्योग को नई गति देने के साथ रोजगार सृजन का बड़ा केंद्र बनेगा।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से तैयार पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार पार्क का विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल या नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जा सकेगा। इसके लिए लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है तथा योजना की अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है।

पार्क में वस्त्र उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही रेडीमेड प्लग एंड प्ले शेड, आंतरिक सड़कें, विद्युत वितरण व्यवस्था, जल एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन, कामन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी), गोदाम, लाजिस्टिक सुविधाएं, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास केंद्र, श्रमिक हास्टल, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामान्य प्रसंस्करण केंद्र विकसित किए जाएंगे।

हथकरघा व वस्त्र उद्योग के सहायक आयुक्त सर्वेश शुक्ला ने बताया कि सहकारी कताई मिल संघ की ओर से पुराना भवन ध्वस्त करने की निविदा की गई है। भवन ध्वस्त होने के साथ ही मौके से पुरानी मशीनरी को भी हटाया जाएगा। इसके बाद बाउंड्रीवाल आदि बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। इन कार्यों में अभी एक महीने से अधिक समय लग सकता है।

बिजली, पानी, सड़क का मांगा प्रस्ताव

प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क के विकास के लिए हथकरघा व वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए बिजली, पानी आपूर्ति व सड़क निर्माण का प्रस्ताव संबंधित विभागों से मांगा गया है। इसके लिए विभाग की ओर से पत्र तैयार कर योजना की जानकारी देते हुए संबंधित विभागों को कार्ययोजना बनाने के लिए कहा गया है।

पार्क में सहायक उद्योगों को मिलेगा स्थान

पार्क में केवल वस्त्र निर्माण इकाइयां ही नहीं बल्कि सहायक उद्योगों को भी स्थान मिलेगा। इनमें बटन, जिपर, फास्टनर, ट्रिम्स, लेबल एवं टैग निर्माण, पैकेजिंग सामग्री, तकनीकी वस्त्र, गोदाम तथा अन्य संबंधित उद्योग शामिल होंगे। योजना के अनुसार पार्क में न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी और किसी एक इकाई को कुल औद्योगिक भूमि का 40 प्रतिशत से अधिक आवंटित नहीं किया जाएगा।

कौशल विकास, प्रयोगशाला, प्रदर्शनी

पार्क निर्माण से पहले पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट में प्रशासनिक भवन, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, कौशल विकास केंद्र, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, विपणन एवं प्रदर्शनी केंद्र, खुदरा सुविधाएं, ट्रक पार्किंग, औद्योगिक श्रमिक आवास, कामन कैंटीन, फायर स्टेशन और हरित क्षेत्र जैसी व्यवस्थाओं का भी प्रस्ताव किया गया है। इससे एक ही जगह सभी सुविधाएं मिल सकेंगी।

लखनऊ में 20 दिन से लापता बेटी की तलाश में भटक रहा परिवार, मतांतरण और सीरिया ले जाने का आरोप

(जीएनएस)।

लखनऊ। पीजीआई इलाके से 21 मई को लापता हुई पीजीआई अस्पताल कर्मी की बेटी का लगभग 20 दिन बाद भी कोई पता नहीं चला। पिता ने अस्पताल परिसर में रहने वाले इरशाद अली नाम के युवक पर 22 मई को बेटी को बहला-फुसला कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था।

मंगलवार को युवती के पिता ने आरोप लगाया कि इरशाद ने जबरन बेटी का मतांतरण कराया और उसे लेकर सीरिया चला गया। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मामले में पुलिस के साथ ही एटीएस और अन्य एजेंसियों ने भी जानकारी जुटाई है।

चार टीम आरोपित और लापता युवती की तलाश में दबिश दे रही हैं। मंगलवार को थाने पहुंचे युवती के पिता रोते-रोते इंस्पेक्टर के कार्यालय के बाहर ही गिर गए। लोगों ने किसी तरह उन्हें संभाला।

युवती के पिता और मां ने बताया कि बेटी 21 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी। पिता का आरोप है कि इरशाद अली पीजीआई परिसर में ही जीव-जंतु पकड़ने का काम करता था। वह लंबे समय से बेटी को परेशान कर रहा था।

इसी दौरान उसका परिवार से संपर्क हुआ और वह बेटी के पीछे पड़ गया। बेटी की अश्लील फोटो एडिट कर ब्लैकमेल करने लगा। पिता का कहना है कि कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

उनका कहना है कि आरोपित के खिलाफ पहले से पीजीआई थाने में मुकदमे दर्ज हैं, इसके बावजूद उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। कुछ समय पहले उसने दबाव बनाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा भी किया था।

पिता का कहना है कि इंटरनेट मीडिया और अन्य माध्यमों से मिल रही सूचनाओं के कारण उन्हें डर है कि कहीं उनकी बेटी का धर्मांतरण कर निकाह कराने की तैयारी तो नहीं की जा रही।

उन्होंने यह भी आशंका जताई कि कहीं आरोपी उसे सीरिया या किसी अन्य देश में तो नहीं ले गया। पिता ने जल्द बेटी की बरामदगी की मांग की है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण अमित कुमार आनंद ने बताया कि मामले की जांच में चार टीम लगी हैं। सीरिया ले जाने की बात निराधार है।

थाने पहुंचे पीजीआई पीजीआई अस्पताल के कई कर्मचारी

मामले को लेकर पीजीआई और चिकित्सा संस्थान के कर्मचारियों में भी नाराजगी है। परिवार के समर्थन में नर्सिंग एसोसिएशन खुलकर सामने आया है।

एसोसिएशन की अध्यक्ष लता सचान, महामंत्री विवेक, सचिव मनोज वर्मा, मंजू लता सहित बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मचारी मंगलवार की शाम पीजीआई थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से युवती की जल्द बरामदगी की मांग की।

एडीएम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस

(जीएनएस)।

लखनऊ, लखनऊ के नरही स्थित करीब 90 साल पुराने विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल को लेकर चल रहे विवाद में एडीएम (नगर पूर्वी) कोर्ट के आदेश के बावजूद बुधवार को स्कूल का ताला नहीं खुल सका। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) द्वारा एसीपी को पत्र भेजे जाने के बाद भी हजरतगंज थाने की पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों को भीषण गर्मी में घंटों स्कूल के बाहर इंतजार करना पड़ा।

एडीएम कोर्ट ने ताला खुलवाने के दिए थे निर्देश

एडीएम (नगर पूर्वी) की अदालत ने 8 जून को पारित अंतरिम आदेश में नरही स्थित विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल का ताला खुलवाने और विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित कराने के निर्देश दिए थे। अदालत ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए छात्रों के हित को देखते हुए विद्यालय को तत्काल प्रभाव से संचालित कराने पर जोर दिया।

स्कूल में ताला लगने से लगभग 250 बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। भीषण गर्मी में स्कूल के बाहर छात्र और शिक्षकों को इंतजार करना पड़ा।

डीआईओएस ने एसीपी को लिखा पत्र, फिर भी नहीं पहुंची पुलिस

कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने मंगलवार को संबंधित एसीपी को पत्र भेजा, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इससे कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्कूल के बाहर भीषण गर्मी में इंतजार करते रहे छात्र और अभिभावक

विद्यालय का ताला नहीं खुलने के कारण शिक्षक, छात्राएं और उनके अभिभावक घंटों तक भीषण गर्मी में स्कूल परिसर के बाहर इंतजार करते रहे। अभिभावकों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है।

कब्जा दिलाने में दिखाई थी तत्परता, अब आदेश के पालन में सुस्ती

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब स्कूल परिसर का कब्जा दिलाने का मामला सामने आया था, तब पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन अब एडीएम कोर्ट के नए आदेश के बाद स्कूल खुलवाने में लेटलतीफी की जा रही है।

कंप्यूटर समेत शैक्षणिक सामग्री को पहुंचा था नुकसान

बताया जा रहा है कि कब्जा दिलाने के बाद स्कूल परिसर के अंदर तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें कंप्यूटर और शिक्षा से जुड़ी अन्य सामग्री क्षतिग्रस्त हो गई थी। इससे स्कूल के संचालन पर भी असर पड़ा है।

90 साल पुराने संस्थान को लेकर जारी है विवाद

नरही स्थित विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल एक पुराना शैक्षणिक संस्थान है और इसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। एडीएम कोर्ट के ताजा आदेश के बावजूद स्थानीय पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने से मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

पहले वर्ष की मेरिट पर मिलेगी स्कूटी, सीएम की नाराजगी के बाद विभागीय प्रक्रिया में आई गति

(जीएनएस)।

लखनऊय यूपी में अब पहले वर्ष की मेरिट पर स्कूटी मिलेगी। सीएम योगी की नाराजगी के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को स्कूटी देने से जुड़ी प्रक्रिया गति पकड़ने लगी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद उच्च शिक्षा विभाग की ओर से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को स्कूटी देने से जुड़ी प्रक्रिया गति पकड़ने लगी है। विभाग ने पहले साल की मेरिट के आधार पर छात्राओं को स्कूटी देने का प्रस्ताव तैयार किया है।

ऐसा इसलिए ताकि छात्राएं आगे की पढ़ाई आसानी से पूरी कर सकें। विभाग ने मंगलवार को सीएम के सामने इसका प्रस्तुतीकरण किया लेकिन अंतिम सहमति नहीं बनी।

सीएम ने कुछ और डाटा के साथ प्रस्ताव पेश करने को कहा।

प्रदेश सरकार ने पिछले साल के बजट में 400 करोड़ का प्रावधान करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की थी। इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा की थी। किंतु उच्च शिक्षा विभाग इस पर एक साल कोई काम नहीं कर सका।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में बजट प्रावधान करते हुए, योजना को जल्द प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।जल्द ही विभाग की ओर से इस प्रस्ताव को सीएम के सामने रखा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू करने की आगे की औपचारिकता पूरी की जाएगी। विभाग की ओर से किए गए बजट प्रावधान के अनुसार लगभग 30 हजार छात्राओं को स्कूटी दी जा सकेगी।